

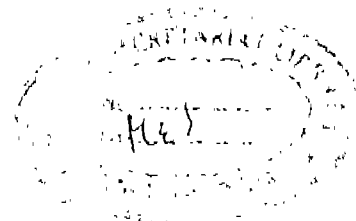


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 150]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1996/फाल्गुन 21, 1917

No. 150]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1996/PHALGUNA 21, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1996

का० आ० 178 (अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन आंध्र प्रदेश कॉटन एसोसिएशन, गुंटूर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को रुई में अग्रिम संविदाओं (एन टी एस डी सी) के बारे में 8-3-1996 से 31-3-1997 (दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाएं।

[मिसिल सं० 12/1/आई० टी०-95]

अशोक कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1996

S.O. 178(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Andhra Pradesh Cotton Association, Guntur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period from the 8th March, 1996 to the 31st March, 1997 (both days inclusive) in respect of forward contracts (NTSDC) in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)/IT/95]

ASHOK KAPUR, Jt. Secy.

568 GI/96

